खतरा | विशेषज्ञ बोले- खत्म हो जाएगा बाघ और हाथियों का कुनबा, कोर-बफर में 500 एकड़ में हो रहा निर्माण कार्य

कागज पर रोक, जमीन पर निर्माण, बन रहे 125 रिसॉर्ट

चिल्हारी नवभारत 3 जून। बांधवगढ़ में बाघ संकट में हैं। कोर और बफर में ताबड़तोड़ होम स्टे, होटल और रिसॉर्ट बन रहे है। इससे ईको-सेंसटिव जोन भी खातरे में है। पत्रिका ताला, मगधी, मझोली व पन्पचा रेज के कोर और कष्पफर एरिया से लगे रंडा, मझोली, पतौर, महामन, मंजराहा, गुरवाही, कथली पहुंचा तो चौकाने वाले तथ्य सामने आए। यहां करीब 125 नए होम स्टे, होटल, रिसॉर्ट बन रहे हैं

स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 500 एकड़ से अधिक भूमि पर निर्माण हो रहा है। सभी जमीन कोर से लगी हैं। कुछ निर्माण जंगल के अंदर कई किमी तक पहुंच चुके हैं। पहले से ही बांधवगढ़ के आसपास 55 होटल व रिसॉर्ट चल रहे हैं। अब नए निर्माण से बाहरी क्षेत्र का भूगोल बदल रहा है। इनमें से कई निर्माण एजेंसियां दक्षिण भारत की हैं।

वन्यजीवों के प्राकृतिक मार्ग अवरुद्ध हो रहे

बांधवगढ़ में हाथियों का मूवमेंट लगातार बढ़ा है। पनपथा और आसपास के क्षेत्र हाथी और बाघ दोनों के लिए अहम रूट मार्ग माने जाते हैं, लेकिन अब इन्हीं रूटों पर रिसॉर्ट, बाउंड्रीवॉल, सड़के और निजी ढांचे खड़े हो रहे हैं। इससे वन्यजीवों के प्राकृतिक मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है। हाथी और बाघ के हमलों से लगातार मौतें हो रही हैं। जल स्रोतों दबाव बढ़ रहा है। जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र खंडित होने का खतरा है।

बीट गार्ड व रेंजर पर सवाल

बिना वन अमले की जानकारी के जंगल में निर्माण संभव नहीं है। नवभारत को कई जगह निर्माण में कीमती लकड़ी का उपयोग भी दिखा। स्थानीय लोगों ने बताया वनकर्मियों व रसूखदार निवेशकों की सांठगांठ से कीमती लकड़ी का चोरी छिपे उपयोग हो रहा है। निर्माण के लिए जंगल की नदियों-नालों से अवैध रेत भी निकाले जा रहे हैं।

जंगल के अंदर बन रहीं सड़कें

रिसॉर्ट के साथ कई जगह नई सड़कें बन रही हैं। यूं तो यह पर्यटकों व निजी वाहनों के लिए बन रही हैं। लेकिन इससे रिसॉर्ट-होटलों तक पड़ेगा। दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। पहुंच भी आसान होगी। जंगल में सड़कों का नेटवर्क बढ़ने से वन्यजीवों के मूवमेंट पर सीधा असर होगा।

आदिवासियों की जमीन का भी हो रहा उपयोग

खास बात यह है कि जंगल के अंदर या इससे लगी कई राजस्व भूमि निजी हैं। इन्हें खरीदकर या लीज पर लेकर रिसॉर्ट बनाए जा रहे हैं। कई मानलों में आदिवासियों की जमीनों का उपयोग निवेशक व प्रभावशाली लोग कर रहे हैं। आयकर विभाग ने भी बफर में आदिवासी भूमि के बेनामी सौदों की जांच की थी। सवाल है. इतने निर्माण को अनुमति कौन दे रहा है।

इनका कहना है

इनका कहना है
अभी किसी तरह निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसे ईको सेंसटिव जोन में शानिल किया गया है। इसके लिए कमेटी बनेगी। इसमें फील्ड डायरेक्टर, कमिश्नर ही अनुमति दे सकते हैं।
राखी सहाय, कलेक्टर उमरिया

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शिफ्ट हुआ हिंसक हाथी

सैटेलाइट कॉलर से की जा रही निगरानी

चिल्हारी नवभारत 3 जून। अनूपपुर और शहडोल जिलों में तीन लोगों की मौत का कारण बने हाथी को अब बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व में शिफ्ट कर दिया गया है। रेस्क्यू के बाद यह हाथी अपने नए प्राकृतिक आवास में धीरे-धीरे खुद को ढालने की कोशिश कर रहा है।

बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व में मौजूद अधिकारियों के अनुसार, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से आए इस हाथी को 23 मई को दक्षिण शहडोल के जंगल क्षेत्र से रेस्क्यू किया गया था। रेस्क्यू के बाद उसे सुरक्षित तरीके से खितोली रेंज के जंगल में छोड़ा गया। बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व के फील्ड डायरेक्टर अनुपम सहाय ने बताया कि हाथी को ट्रैक करने के लिए उस पर सैटेलाइट कॉलर लगाया गया है।

वन विभाग की टीम हाथी की गतिविधियों पर रख रही नजर-सैटेलाइट कॉलर से मिली जानकारी के आधार पर टीम उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे जंगल क्षेत्रों में अनावश्यक प्रवेश न करें और वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। कुल मिलाकर, यह कदम मानव और वन्यजीव संघर्ष को कम करने की दिशा में एक प्रयास माना जा रहा है, लेकिन हाथी की गतिविधियों पर नजर रखना अभी भी वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

बांधवगढ़ में 70 हाथियों की मौजूदगी है

अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल यह हाथी अकेला घूम रहा है और अभी तक किसी अन्य हाथियों के झुंड में शामिल नहीं हुआ है। बांधवगढ़ में लगभग 70 हाथियों की मौजूदगी है, लेकिन यह नया हाथी अभी तक उनके समूह से अलग ही रह रहा है। मुख्य सचिव वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जंगल के नए वातावरण में ढलने में समय लगता है, इसलिए उसकी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

एक नजर में

बंदरों के बढ़ते आतंक से ग्रामीण परेशान

चिल्हारी, नवभारत। मानपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम चिल्हारी गांव में इन दिनों बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बंदरों के झुंड गांव की गलियों, घरों और खेतों में घुसकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बंदर फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ घरों में रखे खाद्यान्न और अन्य सामान भी उठा ले जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार बंदर लोगों को काट भी लेते हैं, जिससे ग्रामीणों में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बंदरों के हमलों के डर से लोग अपने दैनिक कार्यों में भी परेशानी महसूस कर रहे हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि गांव का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर बंदरों के आतंक से राहत दिलाने तथा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

चिल्हारी नवभारत। जिले के मानपुर जनपद अंतर्गत अमरपुर चौकी के ग्राम देवगवा में एक 35 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बुधवार को सुबह आम के पेड़ लटकता हुआ उसका शव मिला। मृतक की पहचान तीरथ यादव निवासी ग्राम कुदरी के रूप में हुई। मृतक अपनी ससुराल गांव देवगवा में रहता था और मंगलवार को ही अपने गृह ग्राम कुदरती से ससुराल गांव देवगवा आया था। बताया जा रहा है कि युवक ने अपने ही गमछे से आम के पेड़ में फंदा बनाकर आत्मघाती कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही अमरपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

हनुमान पहाड़ी मंदिर में छाया पेयजल संकट, भक्त परेशान

चिल्हारी नवभारत 3 जून। चिल्हारी क्षेत्र के प्रसिद्ध हनुमान पहाड़ी मंदिर में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। मंदिर परिसर में लगा एकमात्र हैंडपंप पानी के अभाव में पूरी तरह सूख गया है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हनुमान पहाड़ी मंदिर आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन-पूजन के लिए पहुंचते हैं। विशेष अवसरों और धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन पेयजल की व्यवस्था ठप होने से लोगों को दूर-दराज से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

प्रशासन ने नहीं की ठोस पहल-स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग और प्रशासन का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। भीषण गर्मी के बीच सूखा हैंडपंप श्रद्धालुओं के लिए बड़ी समस्या बन गया है।

तत्काल नया हैंडपंप उत्खनन की मांग-ग्रामीणों, मंदिर समिति और श्रद्धालुओं ने प्रशासन से मांग की है कि मंदिर परिसर में तत्काल नया हैंडपंप उत्खनन कराया जाए, ताकि पेयजल संकट का स्थायी समाधान हो सके।

निरीक्षण में मिलीं मेला-प्रदर्शनी में गंभीर खामियां

झूले बंद रखने के निर्देश, विद्युत एवं फायर सेफ्टी व्यवस्था तत्काल दुरुस्त करने के आदेश

डिंडोरी, नवभारत 3 जून। कलेक्टर अंजू पवन भादौरिया डिंडोरी के निर्देश एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डिंडोरी के मार्गदर्शन में नगर निकाय क्षेत्र में आयोजित मेला एवं प्रदर्शनी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेले में आने वाले नागरिकों की सुरक्षा एवं सुविधाओं का जायजा लिया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण कमियां सामने आईं।

निरीक्षण के दौरान प्रदर्शनी स्थल पर विद्युत व्यवस्था अव्यवस्थित पाई गई तथा कई स्थानों पर खुले तार पाए गए, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इसके अतिरिक्त आगंतुकों के लिए पर्याप्त शौचालय व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। सुरक्षा की दृष्टि से फायर सेफ्टी उपकरण एवं अग्निशमन व्यवस्था का अभाव भी पाया गया, वहीं आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित निकासी के लिए एग्जिट प्वाइंट्स एवं दिशा-सूचक संकेतक भी पर्याप्त रूप से नहीं लगाए गए थे।

आपातकालीन निकास मार्गों को चिन्हित किया जाए

मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित आयोजकों एवं अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। निर्देशित किया गया कि विद्युत व्यवस्था को सुरक्षित एवं मानकों के अनुरूप बनाया जाए, पर्याप्त शौचालय स्थापित किए जाएं, फायर सेफ्टी एवं अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा आपातकालीन निकास मार्गों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाए।

सुरक्षा एवं सुविधाएं सर्वोच्च प्राथमिकता

नगर निकाय द्वारा स्पष्ट किया गया कि नागरिकों की सुरक्षा एवं सुविधाएं सर्वोच्च प्राथमिकता हैं तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण होने के उपरांत ही मेले एवं प्रदर्शनी का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाएगा। साथ ही एहतियातन मेला परिसर में संचालित झूलों को आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

प्रदूषण बोर्ड ने ली जिले के पर्यावरण को नष्ट करने की सुपारी

निजी कंपनियों और माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिये नियमों से खिलवाड़ का आरोप

आदिवासी बहुल इलाके के ग्रामीणों को नहीं दी जानकारी

आरोप है कि जिन गांवों के लोग सीधे तौर पर इन परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले हैं, उनकी बजाय अन्य क्षेत्रों के लोगों को सुनवाई में बुला कर समर्थन दर्ज कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आदिवासी बहुल इलाके के ग्रामीणों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई और उन्हें पूरी प्रक्रिया से दूर रखा गया।

नवभारत उमरिया 3 जून। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए औद्योगिक गतिविधियां और संसाधनों का उपयोग आवश्यक है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है।

लगातार घटती वर्षा, पेयजल संकट, सूखा और भीषण गर्मी जैसी समस्याएं प्रकृति के अंधाधुंध दोहन का ही नतीजा हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने और संतुलन बनाए रखने के लिए शासन ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया है, लेकिन इस विभाग की कार्यप्रणाली के चलते स्थिति गंभीर होती जा रही है। हाल ही घटनाओं से साबित होता है कि महकमे के अधिकारियों ने ही जिले के पर्यावरण को नष्ट करने की सुपारी ले ली है।

नियमों की कागजी खानापूर्ति

स्थानीय नागरिकों, पर्यावरण विदों और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भ्रष्ट अधिकारी निजी कंपनियों और खनिज माफियाओं के साथ मिलकर नियमों की केवल कागजी खानापूर्ति कर रहे हैं। हाल ही मे पाली जनपद के अर्जुनी और पतनार कला मे प्रस्तावित गंगा खनिज एवं बजरंग पावर की कोयला खदानों के लिए आयोजित पर्यावरणीय जनसुनवाई इसका ताजा उदाहरण है।

टूटने लगे विकास के सपने

जानकारों के अनुसार, जब पाली जनपद क्षेत्र में कोयला खदानों की चर्चा शुरू हुई थी, तब लोगों को उम्मीद थी कि इससे क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा, लेकिन कंपनियों की कार्यप्रणाली ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

सवालों से भाग रहीं कंपनियां

गौरतलब है कि पाली क्षेत्र अपने घने और प्राकृतिक वनों, समृद्ध जैव विविधता, और कल-कल बहती नदियों के लिए जाना जाता है। पर्यावरणविदों का कहना है कि बड़े पैमाने पर कोयला खनन शुरू होने से इस पूरे प्राकृतिक तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। वे चाहते हैं कि खनन शुरू होने से पहले जल, जंगल, जमीन और स्थानीय आबादी पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर स्पष्ट और भरोसेमंद आश्वासन दिया जाए।

पत्थर खदानों में भी धांधली

क्षेत्रवासियों का मानना है कि कुछ ही सालों में ये प्रायवेट कंपनियां कोयला निकाल कर चली जायेंगी और उनके पास बस खण्डहर और खाईयां ही बचेंगी। सूत्रों का दावा है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने खनिज माफियाओं को लाभ पहुंचाने केवल खदानों की ही नहीं, बल्कि अन्य खनिज खदानों से जुड़ी पर्यावरणीय स्वीकृतियों की प्रक्रियाएं भी इसी तरह लुकछिप के पूरी कराई गई हैं। इस खेल मे करोड़ों रुपये के लेनदेन की भी चर्चा है।

प्रभारी बीईओ का ट्रायबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन ने किया स्वागत

करंजिया, नवभारत 3 जून। करंजिया विकास खंड में नवनियुक्त प्रभारी बीईओ अजय राय का बुधवार के दिन ट्रायवल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन जिला डिंडौरी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला संयोजक राम कुमार गर्ग ने किया। इस अवसर पर विकास खंड शिक्षा कार्यालय के कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में शिक्षक गरिमामयी उपस्थिति में शामिल हुए। प्रमुख रूप से इनायत अली सैयद, जिला उपाध्यक्ष राजेश वालरे, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार नामदेव, सुनील शुक्ला, अरूण यादव, शैलेष जैन, श्यामवती, सुखदेव सिंह धुर्वे, संदीप साहू सहित अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

शिक्षक हितों को प्राथमिकता देने की उम्मीद : गर्ग-जिला संयोजक राम कुमार गर्ग ने नवागत बीईओ को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अजय राय के नेतृत्व में शिक्षकों के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित होगा और विकास खंड में शिक्षा की गुणवत्ता को नई दिशा मिलेगी।

61वें वनरक्षक प्रशिक्षण सत्र का दीक्षांत समारोह आयोजित

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला स्थित जैव विविधता प्रशिक्षण केन्द्र में 6 माह चली ट्रेनिंग

चिल्हारी नवभारत 3 जून। जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला स्थित जैव विविधता प्रशिक्षण केन्द्र मे गत दिवस 61वें वनरक्षक प्रशिक्षण सत्र का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया।

समारोह में क्षेत्र संचालक डॉ. अनुपम सहाय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारी, प्रशिक्षण केन्द्र का स्टाफ और प्रशिक्षु वनरक्षक उपस्थित रहे। प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि वर्ष 1980 में स्थापित यह संस्थान वर्तमान में जैव विविधता प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में संचालित है, जहां वनरक्षकों को वन्यजीव प्रबंधन, वन संरक्षण और आधुनिक वानिकी का प्रशिक्षण दिया जाता है।सत्र में बालाघाट वनवृत्त के विभिन्न वनमंडलों से आए 35 वनरक्षकों ने छह माह का दक्षता आधारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इस दौरान उन्हे वन्यजीव प्रबंधन, वन सुरक्षा, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, वन सर्वेक्षण, सामुदायिक वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण विकास, ईको पर्यटन, लेखा कार्य और प्राथमिक उपचार का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

असली अधिकारियों ने कर ली नकली ग्रामीणों की जनसुनवाई

बाहरी लोगों की उपस्थिति और नेताओं को लिफाफा, बजरंग पावर कंपनी के नियंत्रण में प्रदूषण बोर्ड

नवभारत उमरिया 3 जून। जिले के पाली जनपद क्षेत्र मे खुलने वाली बजरंग पावर कंपनी की कोयला खदान को लेकर गत दिवस ग्राम पतनार कला में पर्यावरणीय जनसुनवाई शुक्रवार को संपन्न हो गई। जनसुनवाई के बाद क्षेत्र मे कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

आरोप है कि इस सुनवाई में प्रशासन की ओर से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाली मीनाक्षी इंगले, बजरंग पावर कंपनी के अधिकारी एसडी द्विवेदी तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी तो मौजूद रहे, लेकिन जिस क्षेत्र को खोदकर अरबों का कोयला निकाला जाना है, वहां के वास्तविक ग्रामीणों की संख्या नगण्य रही। कुल मिलाकर इस बार भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों पर पूरी प्रक्रिया को 'सेट' करने के आरोप लग रहे हैं।जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में कुछ जनप्रतिनिधि भी कड़े तेवरों के साथ पहुंचे थे, लेकिन बाद में उनका मिजाज ठंडा पड़ गया। क्षेत्र में चर्चा है कि उन्हें 'लिफाफा' देकर शांत कराया गया। एक दिन पहले भी प्रदूषण विभाग द्वारा इसी तरह सीमित सूचना जारी कर अर्जुनी क्षेत्र में गंगा खनिज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की प्रस्तावित खदान की जनसुनवाई धौरई में करवा ली गई थी।

प्रभावित ग्रामीणों को जानबूझकर दूर रखा गया-स्थानीय लोगों का आरोप है कि कंपनियों के हित में काम करते हुए प्रदूषण विभाग के अधिकारी जानबूझकर प्रभावित ग्रामीणों को इन कार्यक्रमों से दूर रख रहे हैं, ताकि औपचारिकताएं भी पूरी हो जाएं और किसी प्रकार के सवाल-जवाब भी न हों। लोगों ने इसे गंभीर और आपराधिक प्रवृत्ति बताते हुए प्रशासन एवं राज्य सरकार से मामले का संज्ञान लेने की मांग की है।

मांग | आशा-ऊषा और पर्यवेक्षकों ने उठाई आवाज, समय पर वेतन का किया जाए भुगतान, सौंपा ज्ञापन

कटौती पर रोक और 26 हजार न्यूनतम वेतन की मांग

डिंडौरी, नवभारत 3 जून। विगत दिवस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यरत आशा, ऊषा एवं आशा पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रोत्साहन राशि का नियमित भुगतान, वेतन कटौती पर रोक और मानदेय वृद्धि सहित कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं।

आशा-ऊषा- पर्यवेक्षक एकता यूनियन (सीटू) की ओर से दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि प्रदेश भर में आशा एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्यों के बदले मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान न तो समय पर किया जा रहा है और न ही पूर्ण रूप से किया जा रहा है। कई जिलों में तीन-तीन और चार-चार माह तक भुगतान लंबित रहने की शिकायतें सामने आई हैं।

मनमानी कटौती से हजारों कार्यकर्ता प्रभावित

यूनियन का कहना है कि वेतन पर्ची की व्यवस्था नहीं होने के कारण कार्यकर्ताओं को यह भी जानकारी नहीं मिल पाती कि उन्होंने कितनी राशि अर्जित की, कितनी स्वीकृत हुई और कितनी कटौती की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन राशि में मनमानी और अनुचित कटौती की जा रही है। कई मामलों में आंशिक भुगतान कर यह बता दिया जाता है कि पूरा भुगतान हो चुका है, जबकि वास्तविकता में महीनों की राशि बकाया रहती है।

गैर-विभागीय कार्यों का भी उठाया मुद्दा

यूनियन ने आरोप लगाया कि आशा कार्यकर्ताओं पर आयुष्मान कार्ड बनाने सहित कई गैर-विभागीय कार्यों का दबाव बनाया जाता है। कई स्थानों पर सेवा समाप्ति की चेतावनी के चलते आशाओं को अपने निजी खर्च से कंप्यूटर ऑपरेटरों के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनवाने पड़े। संगठन ने मांग की कि ऐसे कार्यों का अतिरिक्त भुगतान किया जाए और भविष्य में गैर-विभागीय कार्य जबरन न कराए जाएं। संगठन का कहना है कि देश के कई राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को 10 हजार या उससे अधिक मानदेय दिया जा रहा है, जबकि मध्यप्रदेश में अभी भी निर्धारित राशि मात्र ?6 हजार है। यूनियन ने राज्य सरकार से तत्काल 10 हजार प्रतिमाह राज्य अंशदान देने और कुल मिलाकर आशाओं को 26 हजार न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही आशा पर्यवेक्षकों के वेतन में भी समानुपातिक वृद्धि की मांग की गई है।

ये हैं प्रमुख मांगें

यूनियन ने सरकार और एनएचएम से निम्नलिखित मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है कि प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आशा एवं पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि का नियमित और पूर्ण भुगतान। वेतन में हो रही अनुचित कटौती पर तत्काल रोक तथा पूर्व में काटी गई राशि का एरियर सहित भुगतान। सभी कार्यकर्ताओं को वेतन पर्ची उपलब्ध कराकर भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, रिक्त आशा पदों पर शीघ्र नियुक्ति, बिना जांच और पक्ष सुने सेवा समाप्ति की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।